

करौली सरकार को लेकर बड़ा खुलासा बाबा ने गांव पर कब्जा जमाने के लिए अंधविश्वास का लिया सहारा, ग्राम को शापित बताकर हड्डी जमीन



मजदूर मोर्चा व्यापे

कानपुर का करौली बाबा आश्रम पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। एकसपांज किए जाने पर अपने दरबार में नोएडा के डॉक्टर की बुरी तरह पिटाई करने वाले कानपुर के संतोष सिंह भद्रौरिया उर्फ करौली सरकार पर एक नया खुलासा हुआ है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करौली गांव पर कब्जा जमाने के लिए इस बाबा ने अंधविश्वास का सहारा लिया। करौली सरकार बाबा ने ग्रामीणों को डराया कि करौली गांव शापित है, और इसे श्राप से बाहर निकालने के लिए हवन अनुष्ठान करना पड़ेगा। करौली सरकार के अंधविश्वास में ढूबे ग्रामीण श्राप के नाम पर डरे हुए हैं। जानकारी सामने आ रही है कि इस वक्त लवकुश आश्रम में 5 अप्रैल से तीन दिवसीय विशाल हवन का आयोजन गांव का श्राप मिटाने के नाम पर किया जाएगा। वहाँ दूसरी तरफ जो सच सामने आ रहा है उसके मुताबिक करौली सरकार के आश्रम से सटी करीब डेढ़ बीघे जमीन को हड्डपने के लिए गांव के शापित होने का अंधविश्वास फैलाया गया है। करौली बाबा जमीन खरीदना चाहते थे, मगर किसान ने जमीन बेचने से साफ इंकार कर दिया था।

बाबा ने ग्रामीणों को डराया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करौली सरकार किसान पर लगातार जमीन बेचने का दबाव बना रहे थे, जिसके बाद लगभग तीन महीने पहले किसान ने आश्रम के बाहर हंगामा भी किया था। कहा जा रहा है कि किसान द्वारा हंगामा किए जाने के बाद गुप्ताएँ करौली सरकार ने पूरे करौली गांव को ही शापित करार दे दिया। इतना ही नहीं आश्रम में आने वाले भक्तों को करौली बाबा ने गांव में किराए पर मिलने वाले कमरों में रुकने से यह कहते हुए मना कर दिया कि यह गांव शापित है, अगर यहाँ रुकेंगे तो श्राप का असर तुम पर भी आ जाएगा। बाबा के फैलाये इस अंधविश्वास के बाद करौली गांव में किराए का धंधा करने वाले ग्रामीणों का धंधा चौपट हो गया।

करौली बाबा ने खरीदी कई बीघा जमीन

करौली सरकार के लगातार खुलासों के बाद कानपुर के लवकुश आश्रम के अंदर की सूचनाएँ लीक होने के डर से एंटी से पहले कर्मचारियों के मोबाइल जमा कराए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कैश काउंटरों पर लगने वाली स्थानीय कर्मचारियों की ड्यूटी भी हटा दी गई है।

अब करौली सरकार के आश्रम में नए युवकों को सख्त आदेशों के बाद ड्यूटी पर तैनात किया गया है। आश्रम से होने वाली अंधाधुंध कमाई को करौली सरकार द्वारा प्लाटिंग और प्रॉपर्टी के कारोबार में लगाने की जानकारी है। कानपुर शहर समेत आसपास के जिलों में भी करौली बाबा ने कई बीघा जमीन खरीदी हुई है।

**हे कुल देवता, मुझे शक्ति देना आप से भी
ज्यादा रंग बदल सकूँ ! बस आपसे यही
प्रार्थना है ।**



गांधी और उनकी डिग्री के बारे में मनोज सिन्हा ने क्या कहा, सच क्या है?

दीपक मंडल

दक्षिण अफ्रीका में कानून की प्रैक्टिस के दौरान की महात्मा गांधी की तस्वीर। तस्वीर में उनके साथ हैं एवं ऐसे एल पोलक जो उस वक्त उनके कलर्क हुआ करते थे। साथ में बैठी रूसी महिला शेलेसिन हैं।

जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को दावा किया कि महात्मा गांधी के पास कानून की डिग्री तो छोड़ दी थी। यहाँ लोहिया पर एक किताब के विमोचन के बाद मनोज सिन्हा ने अपने भाषण की शुरुआत गांधी जी की प्रशंसा से की।

उन्होंने कहा, "पढ़े-लिखे लोगों तक को भ्राति है कि गांधी जी के पास कानून की डिग्री थी, लेकिन गांधी जी के पास कोई डिग्री ही नहीं थी।" जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल ग्वालियर की ईटीएम यूनिवर्सिटी में डॉ. राम मनोहर लोहिया व्याख्यान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। यहाँ लोहिया पर एक किताब के विमोचन के बाद मनोज सिन्हा ने अपने भाषण की शुरुआत गांधी जी की प्रशंसा से की।

उन्होंने कहा, "गांधी ने बड़े-बड़े काम किए, ये अभी बताया गया है। मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, देश को आजादी मिली। क्या-क्या किया। लेकिन सब कुछ जो हासिल हुआ उसके केंद्रबिंदु में एक ही बात थी—सत्य।"

"जीवन भर वो सत्य से बंधे रहे, सत्य के अधीन उन्होंने काम किया, आचरण किया। उनके जीवन के हर पहलू को जर्मांचे आप। इसके अलावा और कुछ नहीं था उनके जीवन में। जितनी चुनौतियां आईं, जितनी परीक्षाएं आईं। सत्य कभी नहीं त्याग और महात्मा गांधी अंतर्धान पहचान लिए। परिणाम हुआ कि राष्ट्रपिता हो गए।"

इस बारे में बात करते हुए मनोज सिन्हा ने महात्मा गांधी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल किया।

उन्होंने कहा, "एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देश में अनेक लोगों और पढ़े-लिखे लोगों को भ्राति है कि गांधी जी के पास लॉ की डिग्री थी। गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी। अभी मैं बताऊंगा। कुछ लोग मंच पर भी आकर प्रतिकार करेंगे। लेकिन मैं तथ्यों के साथ आगे बात करूँगा।"

उन्होंने कहा, "कौन कहेगा कि गांधी जी एजुकेट नहीं थे, शिक्षित नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि किसी में साहस है कि ये बात कह सके। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके पास एक भी यूनिवर्सिटी डिग्री या क्रालिफिकेशन नहीं थी।"

सिन्हा ने कहा, "हमें से कई लोग ये सोचते हैं कि उनके पास कानून की डिग्री थी। लेकिन उनके पास ये नहीं थी। उनकी एकमात्र योग्यता हाई स्कूल डिप्लोमा थी।"

जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल ने कहा, "वो कानून की प्रैक्टिस के लिए क्रालिफाई कर गए थे लेकिन उनके पास कानून की डिग्री नहीं थी, लेकिन देखें कि वो कितने शिक्षित थे कि राष्ट्रपिता बन गए, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ डिग्री की औपचारिकता तक ही न रहे या इसे ही शिक्षा न समझे।"

मनोज सिन्हा ने अपने भाषण में गांधी जी की डिग्रियों के बारे में कहा कि वो इस पर तथ्यों के साथ बात करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई तथ्य नहीं दिया, जिससे उनके दावों की पुष्टि हो।

लेकिन महात्मा गांधी की शिक्षा से जुड़े दस्तावेज़ सिन्हा के दावों के उलट तथ्य पेश करते हैं।



बीबीसी हिंदी ने राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय से जो दस्तावेज़ हासिल किए हैं, उनके मुताबिक गांधी ने लंदन यूनिवर्सिटी से जुड़े लॉ कॉलेज इनर टेप्पल से कानून की पढ़ाई कर डिग्री हासिल की थी।

गांधी को 1891 में बार-एट-लॉ का सर्टिफिकेट जारी हुआ था।

इन टेप्पल में उनके दाखिले का दस्तावेज़ भी है। इस दस्तावेज़ का नंबर 7910 है। इसमें उनके इनर टेप्पल में उनके दाखिले की घोषणा है। इस दस्तावेज़ में एडमिशन का खर्च, स्टैम्प ड्यूटी। लेकिन यहाँ उनकी फीस का भी जिक्र है।

लंदन में कानून की पढ़ाई के बाद गांधी भारत लौटे और बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन यहाँ उनकी वकालत नहीं चली। इन टेप्पल में गांधी जी के दाखिले की घोषणा। इसमें एडमिशन का खर्च, स्टैम्प ड्यूटी। लेकिन यहाँ उनकी फीस का भी जिक्र है।

इन टेप्पल में गांधी जी के दाखिले की घोषणा। इसमें एडमिशन का खर्च, स्टैम्प ड्यूटी। लेकिन यहाँ उनकी फीस का भी जिक्र है।

दस्तावेज़ क्या कहते हैं?

बीबीसी ने राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय से जो दस्तावेज़ हासिल किए हैं, उनमें साल 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट में %गांधी एक वकील के रूप में नामक एक प्रदर्शनी में शामिल किए गए। गांधी जी के आवेदन को प्रति भी है। ये आवेदन उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत शुरू करने के लिए दिया था।

आवेदन 1891 में दिया गया था। इस दस्तावेज़ पर भी गांधी जी के हस्ताक्षर हैं।

लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में गांधी जी की वकालत चल नहीं पाई और वो काठियावाड़ पॉलिटिकल एजेंसी में प्रैक्टिस करने के लिए राजकोट चले गए।

राजकोट पॉलिटिकल एजेंसी के गजट में यहाँ की अदालतों में प्रैक्टिस के लिए दिए गए महात्मा गांधी के आवेदन की सूचना दी गई है।

1892 में जारी एजेंसी की अधिसूचना नंबर -16 में कहा गया है कि बैरिस्टर ऑफ लॉ मिस्टर एम. के. गांधी ने काठियावाड़

पॉलिटिकल एजेंसी की अदालतों में प्रैक्टिस की अनुमति मांगी थी और उन्हें इजाज़त दी गई है।

हालांकि काठियावाड़ में भी उन्हें कानून की प्रैक्टिस में कोई खास सफलता नहीं मिली।

1893 में काठियावाड़ के ए